राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पेट.) संख्या 5005/2024

तेजेंदर पाल सिंह उर्फ टिम्मा पुत्र स्वर्गीय श्री सरदार सुरजीत सिंह, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी 619, विनोबा बस्ती, जिला। श्री गंगानगर (राजस्थान), भारत।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
2. लखविंदर सिंह पुत्र श्री महेंद्र सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी गुलाबी बाग, पुरानीआबादी, जिला। श्रीगंगानगर (राज.)भारत।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री विकास बलिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री नितिन गोकलानी द्वारा सहायता प्राप्त
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, पीपी श्री प्रथ्वीपाल सिंह, थाना प्रभारी, कोतवाली, श्रीगंगानगर श्री हिम्मत जग्गा/पत्नी सुश्री तानिया श्री दीपेश सिंह बेनीवाल श्री दीपक चौधरी, एएजी

माननीय श्रीमान. जस्टिस अरुण मोंगा

आदेश

आरक्षित तिथि: 19/10/2024

उच्चारण तिथि: 16/12/2024

1. लखविंदर सिंह (प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता), जो भारत का नागरिक है, का दावा है कि तेजेंदर पाल सिंह (याचिका कर्ता) भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करता है, इसलिए उसने पुलिस में शिकायत/रिपोर्ट दर्ज कराई है। उक्त शिकायत को बाद में एक प्राथमिकी

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

में परिवर्तित/पंजीकृत कर दिया गया, जिसका यहाँ विरोध किया गया है। याचिका कर्ता स्वयं को सिख धर्म का प्रचारक बताता है और दावा करता है कि उसे सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर द्वारा आधिकारिक तौर पर समन्वयक नियुक्त किया गया है। *धर्म प्रचारक समिति* राजस्थान राज्य के लिए। दूसरी ओर, उनका कहना है कि शिकायतकर्ता एक दूसरे गुरुद्वारे के प्रतिद्वंद्वी द्वारा राज्य मशीनरी का शोषण करने और व्यक्तिगत स्कोर तय करने के लिए लगाया गया एक प्रॉक्सी है। उनका रुख यह है कि उनके खिलाफ आरोप निराधार हैं और प्रतिशोध का हिस्सा हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी, बाद में विस्तार से।

1.1 तत्काल आपराधिक विविध। याचिका पुलिस स्टेशन पुरानी आबादी, जिला गंगानगर में पंजीकृत एफआईआर संख्या 0239/2024 दिनांक 06.07.2024 को रद्द करने और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 और 197 (1) (सी) के तहत कथित अपराधों के लिए सभी परिणामी कार्यवाही के लिए है।

तथ्य

2. संक्षेप में, अनावश्यक विवरणों को छोड़कर प्रासंगिक तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता ने पी.एस. पुरानी आबादी, जिला श्री गंगानगर में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 5 जुलाई, 2024 को लगभग 3:30 बजे, याचिका कर्ता ने बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा से अपने फेसबुक अकाउंट पर एक ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग पोस्ट की। रिकॉर्डिंग में, याचिका कर्ता ने कथित तौर पर लोकसभा में संसद के निर्वाचित सदस्य अमृतपाल सिंह के लिए सहानुभूति व्यक्त की। उक्त सांसद वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है और असम की जेल में बंद है। शिकायतकर्ता के अनुसार, याचिका कर्ता का भाषण राष्ट्र-विरोधी था, खालिस्तान की वकालत करता था और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाता था। याचिका कर्ता पर सोशल मीडिया यानी

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

फेसबुक/व्हाट्सएप पर राष्ट्र-विरोधी सामग्री प्रसारित करने का भी आरोप है, शिकायतकर्ता ने चिंता व्यक्त की कि इससे सार्वजनिक अशांति भड़क सकती है

2.1. वस्तुतः, पुलिस शिकायत में दी गई कथा (जिसे शब्दशः एफआईआर में परिवर्तित किया गया है), उपयुक्त होने के कारण, अंग्रेजी में इस प्रकार अनुवादित है:-

"सेवा में"
स्टेशन हाउस ऑफिसर,
पुलिस स्टेशन पुरानी आबादी,
श्रीगंगानगर.

फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और देश के खिलाफ टिप्पणी कर जनता को गुमराह कर देशद्रोह भड़काने और खालिस्तान की मांग करने के आरोप में आरोपी तेजेंद्रपाल सिंह टिम्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के लिए।

शिकायतकर्ता ने निम्नलिखित बताया है:

1. शिकायतकर्ता एक जाट सिख है और उसकी धार्मिक भावनाओं में आस्था है। शिकायतकर्ता सोशल मीडिया पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आरोपी तेजेंद्रपाल सिंह टिम्मा पुत्र सुरजीत सिंह से जुड़ा हुआ है।
2. यह कि दिनांक 05.07.2024 को समय करीब 03.00-03:30 बजे पुरानी आबादी स्थित गुरुद्वारा बाबादीप सिंह स्थित कार्यालय में बैठकर अभियुक्त तेजेन्द्रपाल सिंह टिम्मा द्वारा अपनी फेसबुक आई.डी. पर एक वीडियो बनाई गई। उक्त वीडियो में अभियुक्त ने तथाकथित अमृतपाल सिंह के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त की, जिसने पंजाब के एक थाने पर कब्जा करके देशद्रोह का अपराध किया था तथा उस अपराध के लिए डिब्रूगढ़, असम की जेल में बंद है, तथा भारत देश के विरुद्ध टिप्पणियां करते हुए भड़काऊ भाषण दिए, खालिस्तान की मांग की जिससे सरकार बौखला जाएगी, जिससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तथा देशद्रोह के नाम पर जनता को संबोधित किया अर्थात् खालिस्तान की मांग की, जिससे देश में अशांति या दंगे होने की संभावना है। आरोपी तेजेन्द्रपाल सिंह

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

टिम्मा द्वारा लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों पर देशद्रोह संबंधी बयान दिए जा रहे हैं, जिससे प्रार्थी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि प्रार्थी एक भारतीय नागरिक है और प्रार्थी भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान है। यदि इसी प्रकार आरोपी खालिस्तान की मांग करता रहेगा तो कभी भी जनता में आक्रोश फैल सकता है, जिससे कोई अप्रिय घटना घट सकती है। आरोपी तेजेन्द्रपाल सिंह टिम्मा के खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों से संबंध हैं और इस संबंध में आरोपी ने अपनी तस्वीरें और वीडियो भी वायरल की हैं, जिनमें वह पूरे देश में सभाओं और कार्यक्रमों में खालिस्तान के झंडे लेकर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इस संबंध में सभी तस्वीरें और वीडियो आवेदन के साथ संलग्न हैं। अब प्रार्थी को यह भी पता चला है कि आरोपी तेजेन्द्रपाल सिंह टिम्मा के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में 25-30 मुकदमे लंबित हैं।

3. यह कि आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर बनाया गया वीडियो गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह श्रीगंगानगर के पदमपुर रोड पुरानीआबादी क्षेत्र में स्थित है, जो पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

4. यह कि आरोपी तेजेन्द्रपाल सिंह ने कलेक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर में कलेक्टर का अपमान किया तथा धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया, जिसका वीडियो आरोपी ने बनाया है। इस घटना से पूर्व आरोपी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने खड़े होकर भी उनका अपमान किया तथा धमकी दी तथा कहा था कि जो भी बीच में आएगा, उसे परिणाम भुगतने होंगे। इससे पूर्व उसने कलेक्टर के सामने भी धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया तथा कहा कि हम डेथ वारंट हैं, जिन्होंने दिल्ली जाकर इंद्रा को मार डाला। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आरोपी तेजेन्द्रपाल सिंह टिम्मा के विरुद्ध फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुप पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, जनता को गुमराह कर देशद्रोह भड़काने तथा देश के विरुद्ध टिप्पणी कर खालिस्तान की मांग करने का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।

कृपया एफआईआर दर्ज करें और पुलिस अधिकारियों पीएस पुरानीबाड़ी, श्रीगंगानगर को आगे की कार्रवाई करने के लिए उचित आदेश पारित करें।"

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

2.2. उपरोक्त शिकायत/रिपोर्ट के आधार पर, यहां आरोपित एफआईआर दर्ज की गई।

3. उपर्युक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वन्द्वी की दलीलें सुनी हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है तथा एफआईआर की विषय-वस्तु का भी अध्ययन किया है। याचिका कर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

4. याचिका कर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास बालिया ने शुरू में ही यह तर्क दिया कि एफआईआर झूठी और तुच्छ है, और दावा किया कि यह एक ही मोहल्ले में स्थित दो अलग-अलग गुरुद्वारों के समूहों के बीच प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम है। उनका तर्क यह है कि शिकायतकर्ता एक अन्य व्यक्ति का निकट सहयोगी है जिसके साथ याचिका कर्ता का विवाद है और यह एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि यह याचिका कर्ता के प्रतिद्वंद्वी के प्रतिनिधि के कहने पर दर्ज की गई है।

5. उन्होंने दलील दी कि शिकायतकर्ता ने इसी रंजिश के चलते पहले भी दो झूठी एफआईआर दर्ज कराई थीं। उन्होंने दावा किया कि संबंधित वीडियो की समीक्षा से पता चलेगा कि याचिका कर्ता ने अलग राज्य की मांग नहीं की थी या हिंसा नहीं भड़काई थी, बल्कि केवल राजनीतिक हस्तियों की आलोचना की थी। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर में कोई दम नहीं है और यह याचिका कर्ता को परेशान करने का एक प्रयास है।

6. आगे बताते हुए, याचिका कर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि 05/07/2024 के वीडियो की सामग्री के मात्र अवलोकन से, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बीएनएस, 2023 की धारा 152 या 197(1)(सी) के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है क्योंकि याचिका कर्ता के कथित कृत्य को अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या भड़काने का प्रयास करने या अलगाववादी गतिविधि को प्रोत्साहित करने या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने के बराबर नहीं कहा जा सकता है। याचिका कर्ता ने केवल

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

संसद सदस्य अमृतपाल सिंह के शपथ समारोह से ठीक पहले शपथ लेने की प्रक्रिया के संबंध में संसद में लाए गए संशोधन की आलोचना की है।

6.1. इसके अलावा, बीएनएस, 2023 की धारा 152 के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस धारा में निर्दिष्ट गतिविधियों को उत्तेजित किए बिना या उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना वैध तरीकों से उनमें परिवर्तन प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां उक्त धारा के तहत अपराध नहीं बनती हैं।

6.2. शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित एफआईआर में संदर्भित कथित ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग में अपराध के आवश्यक तत्व स्पष्ट रूप से गायब हैं।

6.3. शिकायतकर्ता ने याचिका कर्ता पर आरोप लगाया है कि उसने भारत के विरुद्ध बयान दिए हैं और संसद के निर्वाचित सदस्य अमृतपाल सिंह के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए खालिस्तान की माँग की है। हालाँकि, कथित एवीआर की विषय-वस्तु के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा एफआईआर में याचिका कर्ता के विरुद्ध लगाए गए ये आरोप कथित वीडियो में मौजूद नहीं हैं और याचिका कर्ता के विरुद्ध दर्ज एफआईआर की पूरी कहानी ही गलत और विकृत है।

6.4. शेष एवीआर के आधार पर आरोपित एफआईआर में याचिका कर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे, अस्पष्ट हैं और बीएनएस, 2023 के प्रभावी होने की तारीख से पहले की घटनाओं के संबंध में हैं, अर्थात 01/07/2024 से पहले।

6.5. बहस के दौरान, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के समक्ष याचिका कर्ता का एक कथित वीडियो चलाया जिसमें वह जंजीरों में जकड़ा हुआ था और राज्य के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था। उन्होंने तर्क दिया कि, प्रासंगिक बात यह है कि याचिका कर्ता केवल राज्य के आचरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था, जिसमें उन कैदियों को

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

रिहा करने से इनकार कर दिया गया था जिन्होंने उस अपराध की अधिकतम सजा पूरी कर ली थी जिसका उन पर आरोप लगाया गया है।

6.6. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि हालांकि शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उपरोक्त घटना श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में हुई थी, लेकिन राज्य के किसी भी अधिकारी ने उक्त घटना के लिए याचिका कर्ता के खिलाफ कोई एफआईआर/शिकायत दर्ज नहीं की है, जिसके बारे में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हैं। यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करता है कि शिकायतकर्ता द्वारा कथित घटना का संस्करण बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत है।

6.7. याचिका कर्ता द्वारा चलाया/दिखाया गया उक्त वीडियो वर्ष 2016 का है। इसलिए, यदि एफआईआर में निहित उक्त आरोपों को वैसे ही लिया जाए, तो भी यह बी.एन.एस 2023 के प्रावधानों के तहत अपराध नहीं बनता है, जो 1 दिसंबर 2016 से प्रभावी हुआ है। अनुसूचित जनजाति जुलाई, 2024। बीएनएस, 2023 एक मूल आपराधिक कानून होने के कारण इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, याचिका कर्ता पर बीएनएस 2023 के तहत उस कृत्य के लिए आरोप नहीं लगाया जा सकता जो उस समय किया गया था जब बीएनएस 2023 लागू नहीं था। इसलिए, उन आरोपों पर आधारित एफआईआर कानून की नज़र में टिक नहीं सकती, उन्होंने ज़ोर देकर तर्क दिया।

6.8. वैसे भी, आरोपित प्राथमिकी में निहित उक्त आरोप 6-7 वर्षों की असाधारण और अस्पष्ट कृत देरी के बाद लगाए गए हैं। चूँकि राज्य प्राधिकारियों या शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष 2016 या उसके बाद संबंधित समय पर याचिका कर्ता के विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए वर्तमान मामले को कृत्रिम रूप से गंभीर बनाने के लिए ही उससे संबंधित आरोपों को वर्तमान प्राथमिकी में जोड़ा गया है, जो कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है।

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

6.9. वह आग्रह करते हैं कि याचिका कर्ता सिख धर्म में गहरी आस्था रखने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता है और उसे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी कई प्रशंसा/प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं। याचिका कर्ता के प्रति द्वेष रखने वाले शिकायतकर्ता को, 8 वर्ष से अधिक पुरानी कथित घटनाओं/वीडियो का हवाला देकर याचिका कर्ता के विरुद्ध फ़िशिंग या घुमंतू जाँच की माँग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि संबंधित समय पर याचिका कर्ता के विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।

7. अपने उपरोक्त तर्कों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया ***मोहम्मद वाजिद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[1] बलवंत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य[2], जावेद अहमद हजाम बनाम महाराष्ट्र राज्य[3], केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य[4]।***

7.1. याचिका कर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया कि उनके तर्कों के आलोक में और पूर्वोक्त निर्णयों के साथ पढ़ते हुए, आरोपित प्राथमिकी और संपूर्ण अनुवर्ती कार्यवाही को रद्द और अपास्त किया जाना चाहिए।

7.2. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया। ***प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य*** [5] व्हाट्सएप संदेशों के संबंध में

1.2023 Livelaw (SC) 624 : 2023 INSC 683

2.[1995] 0 AIR (SC) 1785

3.[2024] 3 S.C.R. 317 : 2024 INSC 187

4.[1962] 0 AIR (SC) 955

5.(2019) 9 SCC 608, 2019 INSC 939

निम्नलिखित राय दी गई है:-

> *"23. अपीलकर्ता द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों की सामग्री और कथित तौर पर बोले गए शब्दों का विस्तृत विश्लेषण किए बिना, यह स्पष्ट है कि ऊपर बताए गए अपराधों में से कोई भी अपराध नहीं बनता है। <u>संदेश</u>*

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

<u>सार्वजनिक दृश्य में नहीं थे, कोई हमला नहीं हुआ था, न ही अपीलकर्ता ऐसी स्थिति में था कि वह शिकायतकर्ता की इच्छा पर हावी हो सके</u>। इसलिए, भले ही व्हाट्सएप संदेशों और कहे गए शब्दों के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को उनके चेहरे पर स्वीकार कर लिया जाए, एससी/एसटी अधिनियम (जैसा कि तब था) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। इसलिए एफआईआर के चेहरे पर आरोप कथित अपराधों के किए जाने की पुष्टि नहीं करते हैं।

अभियोजन पक्ष की दलीलें

8. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित ने तर्क दिया कि उन्हें तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि याचिका कर्ता एक सीरियल अपराधी है और उसके खिलाफ अतीत में 18 एफआईआर दर्ज की गई थीं।

8.1. अभियुक्त-याचिका कर्ता लगातार अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर राज्य की संप्रभुता के खिलाफ वीडियो बनाता और प्रकाशित करता रहा है। यह इस प्रकार था कि उपरोक्त आरोपों के आधार पर, एक एफआईआर, जिसे यहां रद्द करने की मांग की गई थी, पंजीकृत की गई थी।

8.2. जांच के दौरान यह भी पता चला है कि याचिका कर्ता, अपने वीडियो के माध्यम से, सिख समुदाय के लिए देश के रक्षा बलों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर / हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में मौजूद सिखों का हिस्सा होने का प्रचार कर रहा है। वह डिजिटल माध्यमों के माध्यम से ऐसा कर रहा है, इस प्रकार वह दूसरों को पंजाब राज्य को खालिस्तान राज्य घोषित करने की मांग उठाने के लिए उकसा रहा है जो राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है। उसके ऐसे कृत्यों के कारण, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता में गड़बड़ी की आशंका है।

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

8.3. याचिका कर्ता एक आदतन अपराधी है जिसके विरुद्ध टाडा अधिनियम, मारपीट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के प्रावधानों के तहत कई मामले दर्ज हैं।

8.4. जांच के बाद, याचिका कर्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152, 197(1)(सी) के तहत अपराध प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए गए।

8.5. इसके अलावा, विद्वान पीपी ने यह भी बताया कि याचिका कर्ता जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने से बच रहा है। परिणामस्वरूप, इस तरह की टालमटोल की रणनीति के कारण आगे की जाँच भी शुरू नहीं हो पाई है। विद्वान पीपी ने तर्क दिया कि वर्तमान याचिका इस प्रकार खारिज किए जाने योग्य है।

अनुपालनकर्ता की ओर से तर्क

9. शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील मेसर्स हिम्मत जग्गा और दीपेश सिंह बेनीवाल इस प्रकार प्रस्तुत करते हुए याचिका को खारिज करने की मांग करेंगे:-

9.1. याचिका कर्ता ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने कथित वीडियो (वीडियो संख्या 1) को अपने फेसबुक अकाउंट पर वायरल किया है। इस वीडियो में, उसने कहा है कि अमृतपाल सिंह (जो अब खडूर साहिब (पंजाब) से सांसद हैं और वर्तमान में डिब्रूगढ़ (असम) की सेंट्रल जेल में बंद हैं, संसद में खालिस्तान का नारा लगाएंगे और अब सरकार चीखने-चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। फेसबुक अकाउंट पर उनके 32 हजार फॉलोअर्स हैं। उनके वीडियो को 8.4 हजार लोगों ने देखा है और 77 लोगों ने शेयर किया है। इसलिए, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। वह अमृतपाल सिंह और उनकी टीम के निकट संपर्क में हैं, जैसा कि तस्वीरों से स्पष्ट है। याचिका कर्ता का यह

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

कृत्य बीएनएस, 2023 की धारा 152 और 197((1)(सी) के अंतर्गत आता है। इसलिए, इस अदालत द्वारा आरोपित एफआईआर को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

9.2 यह भी आग्रह किया गया कि इसी मामले में इस न्यायालय से अंतरिम राहत मिलने के बाद याचिका कर्ता ने पुनः अपने फेसबुक अकाउंट पर एक और रील और फोटो अपलोड की, जिसमें टिप्पणी थी "1984 जोधपुर जेल दे बंदी आज दरबार साहब शहीद गैलरी विखेध and "दरबार साहिब स्थित शहीद गैलरी में जोधपुर जेल साथियों के साथ आज की एक यादगार तस्वीर। 1984 का वो सका जिसका कुछ शहीद हुए, कुछ जख्मी हुए, कुछ गिरफ़्तार हुए और कुछ फरार हुए। जंग के आलम मैं होता भी यही है। बाबा बंदा सिंह बहादुर से लेकर बंदी सिंघो की दास्तान हमारे सामने है।"

9.3. उक्त वीडियो मृतक जरनैल सिंह भिंडरावाला की तस्वीर के साथ रिकॉर्ड किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि याचिका कर्ता इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का दुरुपयोग कर रहा है। याचिका कर्ता इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को फिर से भड़काने का प्रयास कर रहा है। इस कृत्य से उसने युवाओं के मन को भी प्रदूषित करने का प्रयास किया है। यह कृत्य भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है औरधारा 152 बीएनएस, 2023 की परिभाषा के अंतर्गत आता है। केवल इसी आधार पर, वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

9.4. पूरा मामला अभी प्रारंभिक चरण में है और मामले के पंजीकरण की तिथि पर किए गए कुछ प्रारंभिक प्रयासों को छोड़कर, जांच आगे नहीं बढ़ाई गई है। गहन जांच के बाद साक्ष्य एकत्र किए जाने चाहिए और सक्षम निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। केवल इसी आधार पर, अदालत दुर्भावना की दलील पर किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है। यदि आरोप सत्य से परे और दुर्भावना से लगाए गए पाए जाते हैं, तो जांच से इसका खुलासा हो

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

जाएगा। इस स्तर पर, जब केवल आरोप और प्रत्यारोप हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं है, यह अदालत जांच के परिणाम का अनुमान नहीं लगा सकती और दुर्भावना के प्रश्न पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। इसलिए, शिकायत/एफआईआर को केवल दुर्भावना की निराधार दलील के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यह मानते हुए भी कि शिकायतकर्ता ने केवल अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण शिकायत दर्ज की है, यह अपने आप में गंभीर आरोपों वाली शिकायत को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं होगा। सबूत एकत्र करने के बाद इसका परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

9.5. इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा किया गया।***विनोद रघुवंशी बनाम. अजय अरोड़ा*** [6] इसमें कहा गया है कि अगर आरोपों में कुछ दम है, तो जाँच को शुरू में ही बंद नहीं किया जाना चाहिए। एफआईआर को उसके अंकित मूल्य पर ही लिया जाना चाहिए। प्रारंभिक चरण में एफआईआर में शामिल आरोपों के गुण-दोष पर विचार करने या आरोपों की सत्यता की जाँच करने का कोई सवाल ही नहीं है। वर्तमान मामले में, याचिका कर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने कथित वीडियो वायरल किया था और उसने खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। इसलिए, तत्काल एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता।

9.6. में दिए गए निर्णय पर आगे भरोसा करते हुए ***सतविंदर कौर बनाम. राज्य-सरकार. दिल्ली के एनसीटी के*** [7] शिकायत के विद्वान वकील ने निम्नलिखित उद्धरण पर जोर दिया:-

6.(2013) 10 SCC 581

7.(1999) 8 SCC 728

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

> *"14. इसके अलावा, कानूनी स्थिति यह भी स्थापित है कि यदि किसी अपराध का खुलासा होता है, तो न्यायालय सामान्यतः मामले की जाँच में हस्तक्षेप नहीं करेगा और कथित अपराध की जाँच पूरी होने देगा। यदि प्राथमिकी में प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा होता है, तो न्यायालय सामान्यतः जाँच नहीं रोकता, क्योंकि ऐसा करना पुलिस की संज्ञेय अपराधों की जाँच करने की वैध शक्ति पर आघात होगा। [पश्चिम बंगाल राज्य बनाम स्वप्न कुमार गुहा, (1982) 1 एससीसी 561 : 1982 एससीसी (क्रि) 283] इस न्यायालय के कई निर्णयों से यह भी स्थापित है कि किसी प्राथमिकी या शिकायत को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए, उच्च न्यायालय को पूरी तरह से शिकायत में लगाए गए आरोपों या उसके साथ दिए गए दस्तावेजों के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा; आरोपों की सत्यता या असत्यता की जाँच करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। [प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार, (1985) 2 एससीसी 370, 395 : 1985 एससीसी (सीआरआई) 180]"*

9.7. अतः शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह सभी संभावनाओं के आलोक में शिकायतकर्ता के मामले का विश्लेषण करे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि दोषसिद्धि टिकाऊ होगी या नहीं और इस आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कार्यवाही रद्द कर दी जानी चाहिए। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री का मूल्यांकन और आकलन करके यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि प्राथमिकी/शिकायत पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती।

9.8. उन्होंने आगे बताया कि याचिका कर्ता ने शिकायतकर्ता के खिलाफ दुर्भावना का बचाव करते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके खिलाफ विभिन्न एफआईआर दर्ज कराई थीं, जिनमें पुलिस ने नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दाखिल की है। शिकायतकर्ता ने याचिका कर्ता और अन्य के खिलाफ पीएस पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर में एक

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

और एफआईआर संख्या 290/2022 भी दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि याचिका कर्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर गुरुद्वारे से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र पुस्तक को ले जाकर दमदमा साहिब में जमा कर दिया था। याचिका कर्ता ने अदालत के आदेशों की भी अवहेलना की है। सिविल सूट संख्या 119/2019 में यथास्थिति के निर्देश के बावजूद, उन्होंने अंतरिम आदेश की प्रयोज्यता की सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए एक वीडियो जारी किया। गुरु ग्रंथ साहिब को जबरन हटा दिया गया, जिसके कारण एफआईआर संख्या 168/2020 दर्ज की गई। इस प्रकार, पुलिस ने एफआईआर संख्या 290/2022 में इस आधार पर नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दायर की कि इसी कारणवश, अवतार सिंह नामक व्यक्ति ने पहले ही पुलिस स्टेशन चूनावढ़, जिला श्रीगंगानगर में एफआईआर संख्या 168/2020 दर्ज करा दी थी। शिकायतकर्ता ने इस मामले में एक विरोध याचिका दायर की है और यह अभी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर के समक्ष लंबित है।

9.9. जगसीर सिंह ने भी याचिका कर्ता के विरुद्ध थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर में धारा 295, 295-ए, 499, 500 आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 222/2020 दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस एफआईआर में फिर से नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। लेकिन शिकायतकर्ता ने इसमें भी विरोध याचिका दायर की है और मामले को चुनौती दे रहा है।

9.10. याचिका कर्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन कोतवाली, श्रीगंगानगर में धारा (एस) 395, 153, 153 (ए) और 153 (बी) आईपीसी के तहत एक और एफआईआर संख्या 198/22 दर्ज की गई थी (तत्काल आपराधिक विविध याचिका के पृष्ठ संख्या 25 पर उपलब्ध)। उसमें भी पुलिस ने नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दायर की। शिकायतकर्ता ने फिर से विरोध याचिका दायर की और मामले को लड़ रहा है। उपरोक्त दो एफआईआर संख्या 198/22 और एफआईआर संख्या 222/20 में याचिका कर्ता के खिलाफ आरोप खालिस्तान के नारे लगाने का है, लेकिन पुलिस ने

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

याचिका कर्ता के दबाव में काम करते हुए नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दायर की है। याचिका कर्ता बचपन से ही खालिस्तान और जरनैल सिंह भिंडरावाला का कट्टर समर्थक है। इस प्रकार के लोग भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए बहुत हानिकारक हैं।

9.11. याचिका कर्ता के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 245 के अंतर्गत दर्ज एक अन्य प्राथमिकी संख्या 88/16 में, उस पर श्रीगंगानगर स्थित गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने का आरोप है। इस प्राथमिकी में भी, पुलिस ने याचिका कर्ता और गुरुद्वारा के अन्य सदस्यों के भय और दबाव में आकर बिना कोई जाँच किए नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस मामले में भी शिकायतकर्ता ने विरोध याचिका दायर की है और मामले का विरोध किया है।

9.12. एक बार जब पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज हो जाती है और प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, तो सूचना देने वाले की दुर्भावना का प्रश्न गौण हो जाता है। जाँच के दौरान एकत्रित सामग्री और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य ही आरोपी के भाग्य का फैसला करते हैं। सूचना देने वाले के विरुद्ध दुर्भावना के आरोप महत्वहीन हैं और अपने आप में कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं बन सकते। धनलक्ष्मी बनाम आर. प्रसन्ना कुमार मामले का संदर्भ दिया गया।[8], बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा[9], रूपन देओल बजाज बनाम कंवर पाल सिंह गिल[10], केरल राज्य बनाम ओ.सी.

8. [1990 Supp SCC 686 : 1991 SCC (Cri) 142]

9.[1992 Supp (1) SCC 222 : 1992 SCC (Cri) 192]

10[(1995) 6 SCC 194 : 1995 SCC (Cri) 1059]

कुट्टन[11], उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ओ.पी. शर्मा[12], रश्मी कुमार बनाम महेश कुमार भादा[13], सतविंदर कौर बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)[14] और राजेश बजाज बनाम

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

दिल्ली राज्य एनसीटी[15] वकीलों ने और भी अधिक मामले कानून जैसे कर्नाटक राज्य बनाम एम. देवेंद्रप्पा का हवाला देते हुए उपरोक्त स्थिति को दोहराया।[16], मध्य प्रदेश राज्य बनाम अवध किशोर गुप्ता[17] और उड़ीसा राज्य बनाम सरोज कुमार साहू[18].

9.13. उपरोक्त निर्णय-कानून के आधार पर, वे इस बात पर ज़ोर देंगे कि यदि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध का संकेत देते हैं, तो सूचना देने वाले की दुर्भावनाएँ अप्रासंगिक हो जाती हैं। याचिका कर्ता ने स्वयं खालिस्तान की वकालत करते हुए एक वीडियो वायरल करने की बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की है, जिससे इस न्यायालय के पास इस याचिका पर विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

9.14. याचिका कर्ता पर 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और ऑपरेशन ब्लू स्टार में शामिल होने और जरनैल सिंह भिंडरावाले से संबंध होने के कारण वह नौ साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है। विभिन्न वीडियो का हवाला देते हुए, वे अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आग्रह करेंगे कि याचिका कर्ता के फेसबुक अकाउंट के एक वीडियो में वह जरनैल सिंह

11[(1999) 2 SCC 651 : 1999 SCC (Cri) 304]

12[(1996) 7 SCC 705 : 1996 SCC (Cri) 497]

13[(1997) 2 SCC 397 : 1997 SCC (Cri) 415]

14[(1999) 8 SCC 728 : 1999 SCC (Cri) 1503]

15[(1999) 3 SCC 259 : 1999 SCC (Cri) 401]

16[(2002) 3 SCC 89 : 2002 SCC (Cri) 539]

17[(2004) 1 SCC 691 : 2004 SCC (Cri) 353]

18[(2005) 13 SCC 540 : (2006) 2 SCC (Cri) 272] , SCC pp. 547-50, paras 8-11

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

भिंडरावाले के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अन्य वीडियो में, अमृतपाल सिंह के साथ, उसने सिख शासन स्थापित करने और बलिदान के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। एक अन्य वीडियो में, याचिका कर्ता ने एक रैली आयोजित की जिसमें प्रतिभागियों ने भिंडरावाले की तस्वीरें प्रदर्शित कीं और युवा सिखों को भिंडरावाले की विचारधारा का अनुसरण करने के लिए प्रभावित करने का प्रयास किया।

9.15. एक टीवी साक्षात्कार में, याचिका कर्ता ने स्वयं ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित विभिन्न जेलों में नौ साल से अधिक समय तक रहने की बात स्वीकार की और पंजाब में सिख शासन की खुलेआम वकालत की।

9.16. याचिकाकर्ता आदतन विरोध प्रदर्शनों को संगठित करके अधिकारियों पर दबाव बनाता है। एक बार तो उसने एक सभा का नेतृत्व करते हुए घोषणा की कि सिख सरकारी नीतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने इंदिरा गांधी की हत्या का भी ज़िक्र किया और कहा कि सिख ही वे लोग हैं जिन्होंने दिल्ली जाकर इंदिरा (प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी) की हत्या की (असी मौत दे आ परवाने है | जिन्होंने दिल्ली जाके इंदिरा ठोकी)

9.17. याचिका कर्ता द्वारा अमृतपाल सिंह के साथ मिलकर खालिस्तान की स्थापना और अलगाववाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई गतिविधियाँ राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती । वीडियो वायरल करने की उनकी स्वीकारोक्ति, एफआईआर रद्द करने से रोकती है। धारा 152 बीएनएस, अलगाववाद, विद्रोह और/या भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए कारावास के रिकॉर्ड और खालिस्तान की वकालत करने वाले वीडियो को बनाने और साझा करने की स्पष्ट स्वीकारोक्ति के साथ, याचिका कर्ता इस न्यायालय से किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

10. संक्षेप में, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील का तर्क होगा कि याचिका कर्ता का आचरण और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की सामग्री और याचिका कर्ता का लहजा और भाव स्वयं बोलने वाले हैं।

10.1. शिकायतकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक, एक स्वर में, याचिका कर्ता के उस भाषण पर पुनः ज़ोर देंगे, जिसे उसने स्वयं फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपलोड किया है। उनका तर्क है कि उक्त भाषण भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 और 197(1)(सी) के तहत वैधानिक रूप से निर्धारित तत्वों को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। इसलिए, वे याचिका को खारिज करने का आग्रह करते हैं।

चर्चा, विश्लेषण और राय

11. दोनों पक्षों को सुनने और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, अब मैं प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करूंगा और आगामी भाग में उनके कारण दर्ज करके अपनी राय दूंगा।

12. सबसे पहले, आइए अभियोजन पक्ष द्वारा लागू की गई दंडात्मक धाराओं को देखें, अर्थात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 और 197(1)(सी), जो इस प्रकार हैं:

> ***"152. भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य।-***
> *जो कोई भी, जानबूझकर या जानबूझकर, मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्य चित्रण द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग द्वारा, या अन्यथा, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है; या ऐसे किसी कार्य में लिप्त होता है या ऐसा करता है, तो उसे आजीवन कारावास या सात वर्ष तक के*

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलापों को उत्तेजित किए बिना या उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना वैध साधनों द्वारा उनमें परिवर्तन प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार के उपायों, या प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई के प्रति अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं बनती हैं।

197. राष्ट्रीय एकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप, दावे:-

"(1) जो कोई, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य चित्रण द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या अन्यथा,—

(क) xxx

(बी) xxx

(ग) किसी धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्य होने के कारण किसी वर्ग के व्यक्तियों के दायित्व के संबंध में कोई दावा, परामर्श, दलील या अपील करता है या प्रकाशित करता है, और ऐसा दावा, परामर्श, दलील या अपील ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच वैमनस्य या शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करता है या पैदा करने की संभावना रखता है;

(डी) xxx

तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा।"

12.1 धारा 152, के अवलोकन से पता चलता है कि इसका उद्देश्य भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना है। इस प्रावधान की उत्पत्ति निरस्त आईपीसी की धारा 124 ए (राजद्रोह) से हुई है। राजद्रोह का अपराध मूल रूप से वर्ष 1870 में (1860 में आईओसी के अधिनियमित होने के 10 साल बाद) ब्रिटिश सरकार द्वारा महामहिम या क्राउन के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष के कृत्यों को दंडित करने के लिए पेश किया गया था। आईपीसी की

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

धारा 124-ए के तहत राजद्रोह के अपराध को हालांकि बीएनएस में खत्म कर दिया गया है, लेकिन धारा 152 में एक नया प्रावधान, कुछ इसी तरह से, संसद में कानून निर्माताओं द्वारा लाया गया है। यह उन कृत्यों या प्रयासों को आपराधिक बनाता है जो अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काते हैं, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यह धारा 124-ए (राजद्रोह) को दूसरे नाम से पुनः प्रस्तुत कर रहा है। यह बहस का विषय है कि दोनों प्रावधानों में से कौन सा, अर्थात निरस्त किया गया (राजद्रोह) या पुनः प्रस्तुत किया गया, अधिक कठोर है। प्रासंगिक रूप से, आईपीसी की धारा 124-ए के तहत सजा या तो आजीवन कारावास या तीन साल तक की जेल थी, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता था। जबकि, बीएनएस की धारा 152 के तहत सजा या तो आजीवन कारावास या सात साल तक की जेल है और इसमें जुर्माना भी अनिवार्य रूप से देना होगा। जैसा भी हो, दोनों प्रावधानों को सख्ती से लिखा गया है, और इसलिए मेरा मानना है कि इरादे (मेन्स रीआ) की एक उच्च सीमा, यह सुनिश्चित करती है कि केवल दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए जानबूझकर किए गए कार्य ही इसके दायरे में आएंगे। इस प्रकार प्रावधान (बीएनएस की धारा 152) को इस तरह से पढ़ा और समझा जाना चाहिए कि यह अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा करे कि कार्य जानबूझकर या जानबूझकर किया जाना चाहिए यानी मेन्स रीआ (इरादा)। कथित कार्य जो अनुभाग के दायरे में आते हैं, वे हैं शब्दों (मौखिक या लिखित) और/या संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व और/या वित्तीय साधनों या किसी अन्य तरीके और/या अलगाव, विद्रोह, या विध्वंसक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और/या ऐसे कार्य जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालते हैं। इस प्रकार प्रावधान राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने और अस्थिरता को रोकने का प्रयास करता है। भारत की विविधता और अलगाववादी आंदोलनों के इतिहास को देखते हुए, विधायिका का उद्देश्य उन कृत्यों पर अंकुश लगाना है जो देश को विखंडित कर सकते हैं।

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

12.2. तदनुसार, धारा 152 का स्पष्टीकरण खंड अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करता है, यह छूट देकर कि सरकारी नीतियों की वैध आलोचना, जिसका उद्देश्य वैध तरीकों से सुधार या परिवर्तन करना है, इस धारा के दायरे में नहीं आती। यह स्पष्टीकरण सरकारी नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त करने वाले व्यक्तियों की रक्षा करता है, जब तक कि उनकी आलोचना विद्रोह या अलगाववाद को न भड़काए। यह अंतर वैध असहमति और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, विशेष रूप से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए किया गया है। इस प्रकार व्याख्यात्मक प्रावधान संतुलनकारी कार्य प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि संप्रभुता बनाए रखने के बहाने वैध राजनीतिक असहमति को दबाया न जाए।

12.3. इस संदर्भ में, याचिका कर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सही रूप से उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं:-

<u>बलवंत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य</u>

> *"उपर्युक्त धारा को सीधे पढ़ने से पता चलता है कि इसका प्रयोग केवल तभी होगा जब अभियुक्त लिखित या मौखिक शब्दों या दृश्य चिह्नों या प्रतिरूपणों आदि द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना उत्पन्न करे या उत्पन्न करने का प्रयास करे। अभियोजन पक्ष के इस साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि ऊपर उल्लिखित नारे अपीलकर्ता द्वारा केवल दो-तीन बार लगाए गए थे और न ही इन नारों से सिख समुदाय के किसी अन्य व्यक्ति या अन्य समुदायों के लोगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया हुई, हमें यह मानना कठिन लगता है कि बिना किसी अन्य कृत्य के, दो-तीन बार ऐसे आकस्मिक नारे लगाने पर राजद्रोह का आरोप स्थापित किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष का यह तर्क नहीं है कि अपीलकर्ता या तो किसी जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे या लोगों को अराजकता फैलाने के लिए उकसाने के*

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

इरादे से नारे लगा रहे थे या इन नारों ने वास्तव में कोई कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा की। हमें ऐसा नहीं लगता कि पुलिस को दो अपीलकर्ताओं द्वारा दो-दो बार लगाए गए आकस्मिक नारों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए था और उनका बहुत अधिक अर्थ निकालना चाहिए था। अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया है कि कोई अशांति नहीं हुई। जो भी हो, वह अपीलकर्ताओं द्वारा नारे लगाने के कारण हुआ था और इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ताओं ने एक-दो बार नारे लगाए, आम तौर पर लोग इससे अप्रभावित रहे और अपनी सामान्य गतिविधियों में लगे रहे। केवल दो व्यक्तियों द्वारा एक या दो बार नारे लगाने को सरकार के प्रति घृणा या असंतोष भड़काने या भड़काने का प्रयास करने के उद्देश्य से नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि भारत में कानून द्वारा स्थापित है, धारा 124 ए आईपीसी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होगी और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से आकर्षित नहीं होगी।

9. जहां तक आईपीसी की धारा 153 ए के तहत अपराध का संबंध है, यह धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या किसी भी अन्य आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने या विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच वैमनस्य या घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करने के लिए दंड का प्रावधान करता है। हमारी राय में केवल जहां लिखित या बोले गए शब्दों में सार्वजनिक अव्यवस्था या कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने या सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने की प्रवृत्ति या इरादा हो, वहां ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए कानून को कदम उठाने की जरूरत है। इस मामले के तथ्य और परिस्थितियां स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि जिस क्षेत्र से अपीलकर्ताओं को नारे लगाते हुए पकड़ा गया था, वहां अपीलकर्ताओं की गतिविधियों के कारण कानून और व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था या शांति और सौहार्द में कोई गड़बड़ी या गड़बड़ी की आशंका नहीं थी। अव्यवस्था फैलाने या लोगों को हिंसा के लिए

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

उकसाने का इरादा भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत अपराध की अनिवार्य शर्त है और अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए इस अपराध में निहित मनःस्थिति (मेन्स रीया) का अस्तित्व साबित करना होगा। इस मामले में, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा तीन नारे बार-बार लगाकर, जैसा कि धारा 153ए के प्रावधानों में परिकल्पित है, उनकी ओर से कोई मनःस्थिति (मेन्स रीया) स्थापित नहीं कर पाया है। इसलिए, धारा 153ए के तहत अपराध नहीं बनता है।

जावेद अहमद हजाम बनाम. महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य. सुप्रीम कोर्ट

"जैसा कि विवियन बोस, जे ने कहा है, अपीलकर्ता द्वारा उसके व्हाट्सएप स्टेटस पर इस्तेमाल किए गए शब्दों के प्रभाव को उचित महिलाओं और पुरुषों के मानकों से आंका जाना चाहिए। हम कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले लोगों के मानकों को लागू नहीं कर सकते। हमारा देश 75 से अधिक वर्षों से एक लोकतांत्रिक गणराज्य रहा है। हमारे देश के लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व जानते हैं। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि शब्द विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देंगे। लागू किया जाने वाला परीक्षण कमजोर दिमाग वाले कुछ व्यक्तियों पर शब्दों के प्रभाव या जो हर शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण में खतरा देखते हैं, का नहीं है। परीक्षण उचित लोगों पर कथनों के सामान्य प्रभाव का है, जिनकी संख्या महत्वपूर्ण है। केवल इसलिए कि कुछ व्यक्ति घृणा या दुर्भावना विकसित कर सकते हैं, यह आईपीसी की धारा 153-ए की उपधारा (1) के खंड (ए) को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।"

केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य:

"26.(2). यह सर्वविदित है कि यदि कानून के कुछ प्रावधानों की एक तरह से व्याख्या करने पर वे संविधान के अनुरूप हो जाते हैं और दूसरी व्याख्या उन्हें असंवैधानिक बनाती है, तो न्यायालय पूर्व व्याख्या के पक्ष में झुकेगा। स्पष्टीकरणों के साथ धाराओं के प्रावधानों

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

<u>को समग्र रूप से पढ़ने पर, यह यथोचित रूप से स्पष्ट हो जाता है कि धाराओं का उद्देश्य केवल ऐसी गतिविधियों को दंडनीय बनाना है जिनका उद्देश्य हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति में अव्यवस्था या अशांति पैदा करना हो या ऐसी प्रवृत्ति हो। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, धारा के मुख्य भाग से जुड़े स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करते हैं कि सार्वजनिक उपायों की आलोचना या सरकारी कार्रवाई पर टिप्पणी, चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, उचित सीमाओं के भीतर होगी और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अनुरूप होगी।</u> केवल तभी जब लिखित या बोले गए शब्द आदि, जिनमें सार्वजनिक अव्यवस्था या कानून व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने की हानिकारक प्रवृत्ति या इरादा हो, कानून सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाता है, इस प्रकार व्याख्या की गई, हमारी राय में, यह धारा व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के हित के बीच सही संतुलन बनाती है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी अधिनियम की व्याख्या करते समय न्यायालय को न केवल प्रयुक्त शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि कानून के पूर्ववर्ती इतिहास, उसके उद्देश्य और उस शरारत को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसे वह दबाना चाहता है, जैसे (1) बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, 1955- 2 एससीआर 603 और (2) आर. एम. डी. चमारबागवाला बनाम भारत संघ, 1957 एससीआर 930। इस प्रकाश में देखा जाए तो हमें इन मामलों में आरोपित धाराओं के प्रावधानों की इस प्रकार व्याख्या करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उनका अनुप्रयोग अव्यवस्था उत्पन्न करने के इरादे या प्रवृत्ति, या कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी, या हिंसा को उकसाने वाले कार्यों तक सीमित हो जाए।''

(जोर दिया गया)

12.4. संक्षेप में, अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को संकीर्ण रूप से तैयार किया जाना चाहिए। ऐसे प्रावधानों को लागू करने के लिए भाषण और विद्रोह या अलगाव की संभावना के बीच एक सीधा और आसन्न संबंध होना चाहिए। वैध असहमति या आलोचना की तुलना

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

राजद्रोह या राष्ट्र-विरोधी कृत्यों से नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, निरस्त आईपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह) से जुड़े मामलों में, आकस्मिक या बयानबाजी राजद्रोह नहीं मानी जाती, जब तक कि वे हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़काने वाली न हों। मेरे विचार से, धारा 152 पर भी यही दृष्टिकोण लागू होगा। इसके व्यापक स्वरूप के दुरुपयोग या अतिक्रमण को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक आवेदन आवश्यक है। इस प्रावधान की व्याख्या संवैधानिक अधिकारों के साथ जोड़कर की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन नहीं करता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रावधान का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ढाल के रूप में किया जाता है, न कि वैध असहमति के खिलाफ तलवार के रूप में।

13. अब हम एफआईआर में लगाई गई दूसरी दंडात्मक धारा यानी बीएनएस की धारा 197 (आईपीसी की धारा 153-बी के अनुरूप) की बात करते हैं। यह धारा एक विधायी उपाय है जिसका उद्देश्य विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी, घृणा या वैमनस्य को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को आपराधिक बनाकर भारत के विविधतापूर्ण समाज के सामंजस्य और एकजुटता को बनाए रखना है। यह प्रावधान राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाली विभाजनकारी और भड़काऊ अभिव्यक्तियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। यह धारा शब्दों (मौखिक या लिखित), संकेतों, दृश्य अभ्यावेदन, इलेक्ट्रॉनिक संचार या किसी अन्य माध्यम से किए गए कृत्यों को लक्षित करती है। यह व्यापक दायरा सोशल मीडिया जैसे आधुनिक संचार चैनलों को संबोधित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। उपखंड (सी) किसी विशेष धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय, जाति या सामुदायिक समूह में उनकी सदस्यता के आधार पर व्यक्तियों के दायित्वों के संबंध में दावे, दलीलों, अपील या परामर्श को प्रतिबंधित करता है,

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

13.1. असामंजस्य पैदा करने की मंशा (मेन्स री) या संभावना इस प्रावधान को लागू करने के लिए केंद्रीय है। यदि आपत्तिजनक कार्य से वास्तविक असामंजस्य पैदा नहीं होता है; तो ऐसे परिणाम की संभावना मात्र मेन्स री को स्थापित करने के लिए, किसी अन्य सामग्री के अभाव में, पर्याप्त नहीं हो सकती है। एक धार्मिक समुदाय के सदस्यों से धार्मिक मतभेदों के आधार पर दूसरे समूह का बहिष्कार करने का आग्रह करने वाले आपत्तिजनक बयानों का समाज पर ऐसा प्रभाव होना चाहिए जिससे हिंसा भड़के, रूढ़िवादिता बनी रहे, और समुदायों के बीच गहरा अविश्वास पैदा हो, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक विखंडन हो। इसकी सख्त व्याख्या अपनाई जानी चाहिए, अन्यथा कानून (बीएनएस की धारा 152 और 197 दोनों) असहमति या आलोचनात्मक राय की वैध अभिव्यक्तियों को दबाने के लिए गलत तरीके से लागू किए जाने के खतरे से भरा होगा, खासकर जाति या क्षेत्रीय असमानताओं जैसे संवेदनशील मुद्दों में। इस प्रावधान को अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। ऐसा भाषण जो आलोचनात्मक हो लेकिन हिंसा या घृणा को भड़काए नहीं, इस धारा के दायरे में नहीं आना चाहिए।

13.2. इस प्रकार आरोपित कृत्य और वैमनस्य या घृणा पैदा करने की संभावना के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। सद्भावना से व्यक्त की गई वास्तविक शिकायतों और दुश्मनी या घृणा भड़काने के दुर्भावनापूर्ण इरादे के बीच अंतर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आईपीसी की धारा 153 ए (प्रकृति में समान) के तहत मामलों में, केवल अलोकप्रिय या विवादास्पद विचारों की अभिव्यक्ति अपराध नहीं बनती है जब तक कि सांप्रदायिक घृणा भड़काने का स्पष्ट इरादा या संभावना न हो। आधुनिक समय में जहां डिजिटल युग में भाषण आदर्श है, सोशल मीडिया के उदय ने ऐसे प्रावधानों को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है क्योंकि प्लेटफार्मों का उपयोग अक्सर विभाजनकारी सामग्री को तेजी से और व्यापक रूप से फैलाने के लिए किया जाता है।

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

कानून को अनाम या छद्म नाम से घृणास्पद भाषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है। प्रवर्तन अधिकारियों को रचनात्मक संवाद या राजनीतिक असहमति को रोकने के लिए संयम और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। उचित न्यायिक निगरानी और "असामंजस्य" तथा "दुर्भावना" जैसे शब्दों की व्याख्या करने के स्पष्ट दिशानिर्देश आवश्यक हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून असहमति के दमन या उत्पीड़न का साधन बने बिना अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करे।

13.3. उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, आइए अब हम इस मामले की बारीकियों पर ध्यान दें। बहस के दौरान, विद्वान वकील ने याचिका कर्ता की दिनांक 05.07.2024 की अपलोड की गई ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग भी एक पेन ड्राइव में प्रस्तुत की, जिसे न्यायालय में चलाया गया। यह रिकॉर्डिंग स्थानीय भाषा (पंजाबी) में है। लिप्यंतरण (अंग्रेजी लिपि में) और दिनांक 05.07.2024 की स्थानीय भाषा की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध होना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:

स्थानीय का लिप्यंतरण:

"संसद में जब 'हिंदू राष्ट्र' का नारा लगा, तो बीजेपी वालों ने तालियाँ मार-मार कर, मेज़ थपथपा कर उसका स्वागत किया। आज आ गया भाई अमृतपाल सिंह, सरकार की चीखें निकल गईं। ओम बिड़ला ने एक दिन पहले बयान जारी किया कि नया संशोधन किया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति शपथ लेने के बाद कोई नारा नहीं लगाएगा। पता था कि आगया पठानदर जो संसद के मंच पर चढ़कर 'खालिस्तान' का नारा लगाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, हर किसी को जवाब देना आता है। आज जिस तरह सरकार की चीखें निकलीं, जिस तरह सरकार मछली की तरह पानी से निकली हुई तड़पी, जो नारे लगाते थे, जो दमगजे मारते थे, आज संसद में दिखाई नहीं दिए। जिस तरह

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

अमृतपाल की शपथ ग्रहण की रस्म निभाई गई, तस्वीरें और वीडियो सिंहासन पर रखने के लिए ली गईं — यह है खालसे का खौफ, यह है दशमेश की कौम का खौफ, और यह खौफ होना भी चाहिए। सरकार को समझना चाहिए कि जिस कौम से तुम पंगा ले रहे हो, यह दशमेश की कौम है, यह 21 को 31 मारने वाली है। आज संसद में जो घटनाक्रम हुआ, उसने साबित कर दिया कि वाकई यह शेरों की कौम है, और शेरों की कौम के सामने गीदड़ कलोलें नहीं कर सकते — खौफ में रहेंगे, और खौफ में रहना भी चाहिए।"

<u>कथित वीडियो की प्रतिलिपि का अंग्रेजी अनुवाद</u>

*संसद के अंदर हिंदू राष्ट्र का नारा लगा और भाजपा वालों ने ताली और मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया। आज भाई अमृतपाल सिंह आए हैं और सरकार बड़बड़ा रही है। ओम बिरला ने एक दिन पहले ही बयान जारी किया था कि शपथ लेने के बाद कोई भी व्यक्ति नारे नहीं लगाएगा।**उन्हें पता था कि एक शरारती व्यक्ति आया है, जो संसद की गैलरी में जाएगा और खालिस्तान के नारे लगाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि देश किसी के बाप का नहीं है, हर व्यक्ति जवाब देना जानता है।**आज सरकार जिस तरह चीखी, वो पानी से निकाली गई मछली की तरह है। जो नारे सरकार पहले लगाती थी, वो आज संसद में नहीं सुनाई दिए।**जिस तरह से अमृतपाल सिंह का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, उसके फोटो और वीडियो तक पर रोक लगा दी गई, उससे पता चलता है कि यह खालसा का डर है, यह दशमेश समुदाय का डर है और यह डर होना चाहिए।**सरकारों को पता होना चाहिए कि जिस समुदाय से आप पंगा ले रहे हैं, वो दशमेश समुदाय है। ये वो समुदाय है जिसने 21 में से 31 रिटर्न दिए थे।**आज संसद में घटी घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह शेरों की कौम है और शेरों के सामने गीदड़ कोई शरारत नहीं कर सकते और वे डर कर ही जिएंगे और डर कर ही रहना चाहिए.*

14. विद्वान लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने एवीआर की सामग्री पर भरोसा किया है, विशेष रूप से याचिका कर्ता के एवीआर दिनांक 05.07.2024 में निम्नलिखित

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

कथनों पर और तर्क दिया है कि यह बीएनएस की धारा 152 और 197 (1) के तहत अपराधों के होने का खुलासा करता है।

> *"उन्होंने कहा, ''उन्हें पता था कि एक शरारती व्यक्ति आया है, जो संसद की गैलरी में जाएगा और खालिस्तान के नारे लगाएगा।*
>
> *xxx xxxx xxx*
>
> *मैंने पहले भी कहा था कि देश किसी के बाप का नहीं है, हर व्यक्ति जवाब देना जानता है।*
>
> *xxx xxx*
>
> *जिस तरह से अमृतपाल सिंह का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, यहां तक कि उसके फोटो और वीडियो पर भी रोक लगा दी गई, उससे पता चलता है कि यह खालसा का डर है, यह दशमेश समुदाय का डर है और यह डर होना चाहिए।*
>
> *(जोर दिया गया)*
>
> *xxx xxx xxx*
>
> *सरकारों को पता होना चाहिए कि जिस कौम से आप पंगा ले रहे हैं, वो दशमेश कौम है। ये 21 रुपये के बदले 31 रुपये देने वाली कौम है। आज संसद में हुई घटना ने साबित कर दिया है कि ये शेरों की कौम है और शेरों के सामने गीदड़ कोई शरारत नहीं कर सकते, ये डरकर ही जिएंगे और डरकर ही रहना चाहिए।*

15. उपरोक्त पर विचार करने से पहले, आइए हम विद्वान सरकारी वकील के इस तर्क के गुण-दोष का विश्लेषण करें कि याचिका कर्ता ने अपना मोबाइल फ़ोन न देकर और फ़ेसबुक का यूज़रनेम व पासवर्ड साझा न करके जाँच में सहयोग नहीं किया। हालाँकि, सुनवाई के दौरान, विद्वान लोक अभियोजक ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.10.2024 के आदेश के अनुसार, याचिका कर्ता ने अपना मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप और फ़ेसबुक अकाउंट का यूज़र

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया था, लेकिन उसका कुछ डेटा डिलीट पाया गया। दिनांक 09.10.2024 का आदेश प्रासंगिक होने के कारण नीचे दिए गए लिंक पर पुनः प्रस्तुत है:-

> *1. दिनांक 22.08.2024 के पूर्व न्यायालय आदेश के अनुसरण में, आज पुनः शुरू हुई सुनवाई में, विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि याचिका कर्ता जाँच में शामिल हो गया है, फिर भी वह जाँच अधिकारी के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि, जाँच अधिकारी द्वारा उसे अपना मोबाइल फ़ोन उसकी सामग्री की जाँच के लिए सौंपने का निर्देश दिए जाने के बावजूद, उसने वह फ़ोन उपलब्ध नहीं कराया है।*
>
> *2. याचिका कर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास बालिया ने निर्देशानुसार प्रस्तुत किया कि याचिका कर्ता ने किसी भी स्तर पर अपना मोबाइल फोन सौंपने पर आपत्ति नहीं की है, लेकिन चूंकि जांच अधिकारी द्वारा इसकी जब्ती की रसीद जारी नहीं की जा रही थी, इसलिए उन्होंने अपना मोबाइल उसे नहीं दिया।*
>
> *3. इस संबंध में, विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि जांच अधिकारी मोबाइल फोन की अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) संख्या नोट करके उसे एक रसीद जारी करेगा, और आवश्यक जांच करने के बाद उसे वापस कर दिया जाएगा।*
>
> *4. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका कर्ता के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट तक पहुँचने के लिए मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता है, जिनका उपयोग उसने एफआईआर के आरोपों के अनुसार, जाँच के अधीन अपने वीडियोग्राफी वाले सार्वजनिक बयान को अपलोड करने के लिए किया था। चूँकि याचिका कर्ता ने पहले ही मोबाइल फ़ोन जमा करने के लिए स्वेच्छा से सहमति दे दी है, इसलिए उसे आवश्यक कार्यवाही करनी होगी।*
>
> *5. हालांकि इस न्यायालय का मानना है कि याचिका कर्ता के व्हाट्सएप और फेसबुक खातों तक पहुंचने के लिए, जांच अधिकारी को मोबाइल फोन के भौतिक कब्जे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि*

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

दोनों खातों को किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जब तक कि उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रदान किए जाते हैं।

6. जैसा भी हो, याचिका कर्ता को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट का यूजर आईडी और पासवर्ड देने का भी निर्देश दिया जाता है, ताकि जांच अधिकारी इसकी जांच कर सकें। अगली सुनवाई की तारीख तक या उससे पहले रिपोर्ट दाखिल की जाए।

7. इसे 18.10.2024 को पोस्ट करें।

8. इस बीच, उपरोक्त अनुपालन के अधीन, संबंधित एफआईआर के संबंध में याचिका कर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।

एसडी/-
(अरुण मोंगा), जे."

16. यह पता चला है कि याचिका कर्ता ने जाँच दल को मोबाइल फ़ोन दिया था। इस स्तर पर, मैं यह कहना चाहूँगा कि याचिका कर्ता द्वारा पहले ही दी गई उपरोक्त जानकारी के आधार पर, पुलिस स्वयं संबंधित सेवा प्रदाता और/या साइबर विशेषज्ञों से हटाए गए डेटा को पुनः प्राप्त कर सकती है। किसी भी स्थिति में, याचिका कर्ता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत चुप रहने का अधिकार है और इस प्रकार सहयोग न करने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

17. जैसा भी हो, याचिका कर्ता का मोबाइल फोन मिलने के बाद भी, याचिका कर्ता के फेसबुक अकाउंट या व्हाट्सएप अकाउंट से किसी भी तरह की आपराधिक साजिश या अन्यथा खोजे गए सबूतों को साबित करने के लिए न तो कुछ रिकॉर्ड में रखा गया है और न ही बहस के दौरान उस पर भरोसा किया गया है। यह दावा भी नहीं किया गया है कि याचिका कर्ता के मोबाइल फोन से हटाए गए डेटा में उसके खिलाफ कोई विशिष्ट सामग्री है। इस बात के किसी भी संकेत/

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

संकेत के अभाव में कि याचिका कर्ता के मोबाइल फोन से हटाए गए डेटा में उसके खिलाफ कोई विशिष्ट सामग्री है, मेरी राय में, यह कहना पूरी तरह से अनुमान होगा कि अगर/जब इसे पुनर्प्राप्त किया जाता है, तो उसके खिलाफ कोई भी दोषपूर्ण सामग्री मिलेगी या नहीं। इसलिए, यह याचिका कर्ता के साथ अन्याय होगा यदि पुलिस जांच को और लंबा खींचकर उसे नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि पुलिस हटाए गए डेटा में कुछ खोजने के प्रयास में एक नौकायन और मछली पकड़ने का अभ्यास कर सके, जो याचिका कर्ता के खिलाफ दोषपूर्ण हो सकता है।

18. प्रासंगिक रूप से, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसने याचिका कर्ता और अन्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर में एफआईआर संख्या 290/2022 दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिका कर्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर गुरुद्वारा से श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ले लिया था और उसे दमदमा साहिब में जमा कर दिया था; जगसीर सिंह ने भी याचिका कर्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन कोतवाली, श्रीगंगानगर में धारा 295, 295-ए, 499 और 500 आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 222/2020 दर्ज कराई थी; याचिका कर्ता के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 245 के तहत एक अन्य एफआईआर संख्या 88/16 में, मामला याचिका कर्ता द्वारा गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह, श्रीगंगानगर में किए गए अवैध अतिक्रमण से संबंधित है और उन सभी एफआईआर में, पुलिस ने अदालतों में नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दायर की है।

18.1. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन नकारात्मक अंतिम रिपोर्टों के खिलाफ विरोध याचिकाएं भी दायर की गई हैं जो लंबित हैं।

18.2. बहरहाल, तथ्य यह है कि एक को छोड़कर, याचिका कर्ता के खिलाफ शेष उपरोक्त एफआईआर प्रतिवादी संख्या 2 (तत्काल मामले में शिकायतकर्ता) द्वारा दर्ज की गई थीं। केवल

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

विरोध याचिकाओं को दायर करना और लंबित रहना इस वास्तविकता को भी नकारता नहीं है कि पुलिस ने याचिका कर्ता के खिलाफ दर्ज उन एफआईआर में पहले ही नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दायर कर दी है। इसलिए, तत्काल आरोपित एफआईआर को शिकायतकर्ता के इरादे और याचिका कर्ता के खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित होने की उचित संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति होने के नाते, आरोपित एफआईआर की सामग्री को जांच के सामान्य मानक से अधिक की आवश्यकता है।

18.3. इसके अलावा, याचिका कर्ता के पूर्ववृत्त के आधार पर, जो अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता द्वारा हमले का प्राथमिक आधार रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है ***<u>मोहम्मद वाजिद, सुप्रा.</u>*** इसका प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> *"राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपनी लिखित प्रस्तुतियों में अपीलकर्ताओं के पूर्ववृत्त के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया है। चार्ट पर एक नज़र डालने से यह आभास हो सकता है कि अपीलकर्ता हिस्ट्रीशीटर और दुर्दांत अपराधी हैं। हालाँकि, जब एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की बात आती है, तो अभियुक्त के आपराधिक पूर्ववृत्त को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने का एकमात्र विचार नहीं किया जा सकता है। एक अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष यह कहने का वैध अधिकार है कि चाहे उसका पूर्ववृत्त कितना भी बुरा क्यों न हो, फिर भी यदि एफआईआर किसी अपराध के होने का खुलासा करने में विफल रहती है या उसका मामला भजन लाल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों में से एक के अंतर्गत आता है, तो न्यायालय को केवल इस आधार पर आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि अभियुक्त एक हिस्ट्रीशीटर है। अभियोजन*

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

शुरू करने से अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्तियों के लिए प्रतिकूल और कठोर परिणाम होते हैं।"

19. उपरोक्त सभी के अलावा, याचिका कर्ता के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई अन्य एफआईआर की उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के मद्देनजर याचिका कर्ता को सौंपी गई एवीआर दिनांक 05.07.2024 की सामग्री को पढ़ने और सुनने के बाद, मेरी राय है कि यह याचिका कर्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 या धारा 197 (1) की प्रयोज्यता को आकर्षित नहीं करती है।

20. आइए अब उन कथित आपत्तिजनक बयानों का विश्लेषण करें जो दंडात्मक धाराओं को लागू करने का कथित कारण हैं। याचिका कर्ता के बयान का वह हिस्सा कि "*एक शरारती व्यक्ति आ गया है, जो संसद की गैलरी में जाकर खालिस्तान के नारे लगाएगा*" केवल इस संभावना को संदर्भित करता है कि कोई अन्य व्यक्ति (अमृतपाल सिंह सांसद) संसद की गैलरी में जाएगा और खालिस्तान के नारे लगाएगा। कल्पना की किसी भी सीमा तक यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिका कर्ता का यह संदेश देने का इरादा था कि वह (तेजिंदरपाल सिंह टिम्मा याचिका कर्ता) खुद खालिस्तान के नारे लगाएगा या जानबूझकर या जानबूझकर अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काएगा या भड़काने का प्रयास करेगा, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करेगा या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालेगा; या ऐसे किसी भी कृत्य में लिप्त होगा या करेगा।

21. याचिका कर्ता के बयान का अगला भाग कि*"मैंने पहले भी कहा था कि देश किसी के बाप का नहीं है, हर आदमी जवाब देना जानता है"*इसका मतलब केवल यही है और यह बताता है कि देश अपने सभी नागरिकों का है, इसके विपरीत इसके सभी नागरिक देश के हैं और सभी नागरिकों के लिए समानता है। बोलचाल की पंजाबी, अपनी समृद्ध और अभिव्यंजक प्रकृति के

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

साथ, हमेशा ही आपत्तिजनक लग सकती है, तब भी जब कोई दुर्भावना या अपमान करने का इरादा मौजूद न हो। यह विशेषता भाषा की अंतर्निहित स्पष्टता और ओज से उपजी है, जिसे कभी-कभी गलत समझा जा सकता है। हालांकि, ऐसी अभिव्यक्तियों को आपराधिक माना जाने के लिए, सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नतीजे या ठोस सबूत होने चाहिए जो किसी भी सार्वजनिक अशांति को फैलाने या हिंसा भड़काने के लिए जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे (मेन्स रीआ) का संकेत दें। किसी बयान को आपत्तिजनक समझना व्यापक संदर्भ या दावे को पुष्ट करने के लिए ठोस नुकसान के बिना अपर्याप्त है।

22. याचिका कर्ता का आगे यह कथन कि "*जिस तरह से अमृतपाल सिंह का शपथ ग्रहण समारोह किया गया, उसकी फोटो और वीडियो तक लेने पर रोक लगा दी गई, उससे पता चलता है कि ये खालसा का डर है, ये दशमेश कौम का डर है और ये डर होना भी चाहिए*" इससे पता चलता है कि याचिका कर्ता केवल वैध तरीकों से उनमें परिवर्तन प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार के उपायों, या प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई पर टिप्पणी कर रहा था और अपनी असहमति व्यक्त कर रहा था, लेकिन इस खंड में निर्दिष्ट गतिविधियों को उत्तेजित किए बिना या उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना।

23. याचिका कर्ता का अगला कथन है कि "*सरकारों को पता होना चाहिए कि जिस कौम से आप पंगा ले रहे हैं, वो दशमेश कौम है। ये 21 रुपये के बदले 31 रुपये देने वाली कौम है। आज संसद में हुई घटना ने साबित कर दिया है कि ये शेरों की कौम है और शेरों के सामने गीदड़ कोई शरारत नहीं कर सकते, ये डर कर ही जिएंगे और डर कर ही रहना चाहिए।*"ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल दसवें सिख गुरु गोबिंद सिंह (दशमेश) के अनुयायियों की बहादुरी, वीरता और उदारता के प्रति उनकी प्रशंसा को व्यक्त करता है।

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

24. मेरे विचार में, 05.07.2024 के एवीआर की समग्र सामग्री बीएनएस, 2023 की धारा 152 के लागू होने को आकर्षित नहीं करती है, जो 01.04.2024 से लागू हुई। यह जानबूझकर या जानबूझकर, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करने या उत्तेजित की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने; या ऐसे किसी भी कृत्य में लिप्त होने या करने के बराबर नहीं है। मेरे विचार से, वे उपायों, या सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियों से अधिक कुछ नहीं हैं, जो कि उक्त धारा के नीचे स्पष्टीकरण में संदर्भित गतिविधियों को उत्तेजित किए बिना या उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना वैध तरीकों से उनमें परिवर्तन प्राप्त करने के उद्देश्य से हैं और जिन टिप्पणियों को इसकी प्रयोज्यता से विशेष रूप से बाहर रखा गया है।

25. मेरा यह भी मत है कि दिनांक 05.07.2024 की एवीआर की समग्रता में सामग्री, बीएनएस की धारा 197(1) के लागू होने को आकर्षित नहीं करती है क्योंकि इसमें ऐसा कोई आरोप नहीं है कि किसी भी धर्म, मूलवंश, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय का सदस्य होने के कारण किसी भी वर्ग के व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा नहीं रख सकते हैं या भारत की संप्रभुता और अखंडता को कायम नहीं रख सकते हैं; या ऐसा कोई दावा, परामर्श, सलाह, प्रचार या प्रकाशन नहीं है कि किसी भी धर्म, मूलवंश, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय का सदस्य होने के कारण किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकारों से वंचित या वंचित किया जाएगा; या किसी भी धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्य होने के कारण किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के दायित्व के संबंध में कोई दावा या सलाह, दलील या अपील और ऐसा दावा या सलाह, दलील या अपील, ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच वैमनस्य या दुश्मनी या घृणा या दुर्भावना की

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

भावना का कारण बनता है या होने की संभावना है; या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी और भ्रामक जानकारी।

26. शिकायतकर्ता के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित अन्य सभी एवीआर (वीडियो क्रमांक 1 से 16) 01.07.2024 से बहुत पहले यानी बीएनएस, 2023 के लागू होने से पहले तैयार और प्रकाशित किए गए थे। कथित आपराधिक कृत्य 01.07.2024 से पहले के थे। उन्हें 06.07.2024 को दर्ज तत्काल एफआईआर संख्या 239/2024 में भी शामिल किया गया है। मेरी राय में, बीएनएस, 2023 के मूल दंड प्रावधान [इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 और धारा 197(1)] याचिका कर्ता के खिलाफ 01.07.2024, इसके लागू होने की तारीख से पहले किए गए या किए गए तथाकथित आपराधिक कृत्यों के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किए जा सकते।

27. *में* ***विजय शर्मा बनाम राज्य***[19]*,*मेरे द्वारा लिखित निर्णय में, मैंने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत 01.07.2024 से पहले किए गए अपराधों के संबंध में, 01.07.2024 से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के लागू होने के बाद (बीएनएस) के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। पुन: प्रस्तुत:-

> *"7. प्रतिद्वंद्वी विवादों से निपटने और उन पर निर्णय लेने के लिए, कानून के निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार और निर्णय की आवश्यकता है:*
>
> *(क) क्या 01.07.2024 से भारतीय न्याय संहिता के लागू होने केबाद, 01.07.2024 से पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत किए गए अपराधों के लिए आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है या नहीं?*

19 2024 SCC Online Raj. 2897 and 2024:RJ-JD:35171

> *(ख) क्या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत 01.07.2024 से पहले किए गए अपराधों के लिए, 01.07.2024 से भारतीय*

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

न्याय संहिता (बीएनएस) के लागू होने के बाद (बीएनएस) के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है या नहीं?

(ग) 01.07.2024 से पहले किए गए आईपीसी के तहत अपराधों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के लागू होने के बाद दर्ज एफआईआर पर कौन सी प्रक्रिया लागू होगी?

8. से 11. xxx xxxx xxx

12. मेरी राय में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और बीएनएस की धारा 358 के पूर्वोक्त बचत प्रावधानों का संयुक्त अध्ययन पर्याप्त रूप से दर्शाता है कि आईपीसी 01.07.2024 से पहले अर्जित या किए गए किसी भी दायित्व, देयता, दंड या सजा पर लागू होगी। दूसरे शब्दों में, 01.07.2024 से पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत किए गए अपराधों के संबंध में, अपराधी को 01.07.2024 से भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद भी आईपीसी के तहत निपटाया और दंडित किया जा सकता है/जाना चाहिए। इस प्रकार, ऐसा लगता है कि 01.07.2024 से पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत किए गए अपराधों के लिए, आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

13. इस संदर्भ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के निर्णय के मामले में ***दीपू एवं अन्य। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।*** [20] *निम्नानुसार आयोजित किया गया है:*

"16. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, यह न्यायालय क्रमशः बीएनएस और बीएनएसएस द्वारा आईपीसी और सीआरपीसी को निरस्त करने के प्रभाव के संबंध में कानून का सारांश भी प्रस्तुत कर रहा है और उसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

(i) यदि 1.7.2024 से पहले किए गए अपराध के लिए 1.7.2024

20 2024 SCC Online All 4289 :(2024), 129ACC127 and 2024 : AHC : 126843-DB

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

को या उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, तो आईपीसी के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी लेकिन जांच बीएनएसएस के अनुसार जारी रहेगी।

(ii) 01.07.2024 (नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की तिथि) पर लंबित जांच में, पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिए जाने तक सीआरपीसी के अनुसार जांच जारी रहेगी और यदि सक्षम न्यायालय द्वारा आगे की जांच के लिए कोई निर्देश दिया जाता है तो वह सीआरपीसी के अनुसार जारी रहेगी;

(iii) 01.07.2024 को या उसके बाद लंबित जांच पर संज्ञान बीएनएसएस के अनुसार लिया जाएगा और जांच, परीक्षण या अपील सहित सभी बाद की कार्यवाही बीएनएसएस की प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी।

(iv) बीएनएसएस की धारा 531(2)(ए) केवल लंबित जांच, परीक्षण, अपील, आवेदन और पूछताछ को ही सुरक्षित रखती है, इसलिए, यदि कोई परीक्षण, अपील, पुनरीक्षण या आवेदन 01.07.2024 के बाद शुरू होता है, तो उस पर बीएनएसएस की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(v) 01.07.2024 को लंबित मुकदमा, यदि 01.07.2024 को या उसके बाद समाप्त होता है, तो ऐसे मुकदमे में पारित निर्णय के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण बीएनएसएस के अनुसार होगा। हालाँकि, यदि कोई आवेदन अपील में दायर किया जाता है, जो 01.07.2024 को लंबित था, तो सीआरपीसी की प्रक्रिया लागू होगी।

(vi) यदि आपराधिक कार्यवाही या आरोपपत्र को 01.07.2024 को या उसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, जहां जांच सीआरपीसी के अनुसार की गई थी, तो उसे बीएनएसएस की धारा 528 के तहत दायर किया जाएगा, न कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत।

14. से 17. xxx xxx xxx

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

18. तदनुसार, ऊपर दिए गए प्रश्न (क) का उत्तर सकारात्मक है। इसके परिणामस्वरूप, यह माना जाता है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत 01.07.2024 से पहले किए गए अपराधों के लिए, 01.07.2024 से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के लागू होने के बाद (बीएनएस) के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। अतः, प्रश्न (ख) का उत्तर नकारात्मक है।

xxx xxx xxx"

28. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले में, दिनांक 05.07.2024 की एवीआर को छोड़कर, शेष एवीआर 01.07.2024 से पहले तैयार और प्रकाशित की गई थीं। यदि कोई अपराध हुआ है, तो वह 01.07.2024 से पहले किया गया था, जिस पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधान लागू होंगे। इस दृष्टि से, 01.07.2024 से पहले किए गए भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों, यदि कोई हो, के लिए बीएनएस, 2023 के प्रावधानों के तहत दिनांक 06.07.2024 की विवादित एफआईआर दर्ज करना अनुचित था। इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि बीएनएस, 2023 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत दिनांक 06.07.2024 की एफआईआर, जो 01.07.2024 से पहले एवीआर तैयार करने और प्रकाशित करने के द्वारा आईपीसी के तहत किए गए कथित आपराधिक कृत्यों और अपराधों, यदि कोई हो, पर आधारित है और उनसे संबंधित है, तो उसे रद्द किया जा सकता है।

29. इसलिए, 01.04.2024 से पहले एवीआर तैयार करके अपलोड करके किए गए कथित आपराधिक कृत्यों के बारे में आगे कोई चर्चा करना न तो आवश्यक है और न ही उचित।

30. उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मेरी राय है कि याचिका कर्ता के खिलाफ आरोपित एफआईआर और परिणामी कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, याचिका कर्ता को अनुचित उत्पीड़न और अपमान का कारण बनता है और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)

करने के लिए, याचिका कर्ता के खिलाफ आरोपित एफआईआर और परिणामी कार्यवाही को रद्द करना एक उपयुक्त मामला है।

31. तदनुसार, याचिका को अनुमति दी जाती है और पुलिस स्टेशन पुरानी आबादी, जिला गंगानगर में दर्ज एफआईआर संख्या 0239/2024 दिनांक 06.07.2024 और याचिका कर्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 और 197 (1) (सी) के तहत अपराधों के लिए सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।

32. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा हो जाएगा।

(अरुण मोंगा), जे

जितेंद्र

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है- हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(30/05/2025 को सुबह 08:45:24 बजे डाउनलोड किया गया)